3 सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास

5 एक साधारण महिला की ऊंची छलांग

7 रिटायरमेंटः यह अनुभव का स्वर्णकाल है

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 29 प्रति सोमवार, 24 नवंबर 2025 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

उज्जैन के किसानों के जिद और जज़्बे के आगे मोहन सरकार नतमस्तक

जगत विजन की ख़बरों का प्रभावी असर, अन्नदाताओं की लड़ाई के लिए पूरे विश्वास से उठाया मुद्दा

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

उज्जैन की पवित्र धरती ने इतिहास में संघर्ष, अस्मिता और जनशक्ति के कई प्रसंग देखे हैं। परंतु इस बार का संघर्ष केवल जमीन का नहीं था यह किसानों के स्वाभिमान, अधिकार और अपने वंशों से जुड़ी मिट्टी के सम्मान की लड़ाई थी। इसी लड़ाई में जीत दर्ज की है उनके अडिग जज्बे, साहस, एकजुटता और न्याय के प्रति अटूट विश्वास ने। सिंहस्थ 2028 के लिए बनाई गई विवादास्पद लैंड पुलिंग परियोजना को अंततः सरकार को वापस लेना पड़ा। यह निर्णय स्वयं सत्ता के शीर्ष स्तर पर बैठे लोगों के लिए किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि यह वो योजना थी जिसके माध्यम से प्रशासन 2378 हेक्टेयर उपजाऊ भूमि पर कब्जे की तैयारी कर चुका था।

सिंहस्थ की तैयारी के नाम पर किसानों की जमीन पर नजर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनका प्रशासन पिछले कई महीनों से सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के नाम पर एक व्यापक भूमि अधिग्रहण योजना का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका था। योजना के तहत उज्जैन के ग्रामीण अंचलों के हजारों किसानों की जमीन को लैंड पुलिंग मॉडल के जरिए अपने अधीन लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। सरकारी भाषा में यह विकास का मॉडल बताया गया, लेकिन किसानों की नजर में यह उनकी पैतृक जमीन को हड़पने का एक सुनियोजित प्रयास था। 2378 हेक्टेयर उपजाऊ भूमि, जो पीढ़ियों से फसलें उगाती आई थी, सिंहस्थ के बहाने विकास के नाम पर सरकार की नजर में चढ़ चुकी थी। इससे किसानों में भय, आक्रोश और असंतोष स्वाभाविक था।

लैंड पुलिंग योजना की वापसी ने खोल दी सत्ता–प्रशासन की कार्यशैली की पोल

किसानों की आवाज को सबसे पहले बुलंद किया 'जगत विजन' ने

जब इस मुद्दे पर मुख्यधारा की मीडिया खामोशी ओढ़े बैठी थी, तब सबसे पहले जगत विजन ने किसानों के दर्द को स्वर दिया। मैंने वह किया, जो बड़ी मीडिया संस्थाएं करने का साहस नहीं जुटा पा रहीं थीं। लैंड पुलिंग परियोजना की खामियों, किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव और प्रशासनिक रवैये को विस्तार से उठाया। पत्रिका में इस मुद्दे को प्रकाशित कर न केवल किसानों को एक मंच दिया बल्कि सरकार तक यह स्पष्ट संदेश भी पहुंचाया कि उज्जैन की मिट्टी कोई मोल–भाव की वस्तु नहीं, बल्कि किसानों की जीवनरेखा है। इस पत्रकारिता ने आंदोलन को नई ऊर्जा और विश्वसनीयता प्रदान की। (शेष पेज 2 पर)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025

एनडीए की ऐतिहासिक जीत और राजद-कांग्रेस का डांवाडोल होता राजनीतिक भविष्य

-विजया पाठक

बिहार में संपन्न हुए 2025 के विधानसभा चुनाव परिणामों ने राज्य की राजनीति की दिशा और दशा दोनों को बदलकर रख दिया है। यह चुनाव सिर्फ दलों की जीत-हार का आंकड़ा नहीं रहा, बल्कि यह बिहार के राजनीतिक मानस, नेतृत्व की स्वीकार्यता और गठबंधन राजनीति की वास्तविकता का स्पष्ट आईना साबित हुआ है। एनडीए की रिकॉर्ड-तोड़ विजय, राजद का निराशाजनक प्रदर्शन और कांग्रेस की लगभग अप्रासंगिक होती उपस्थिति मिलकर एक नया राजनीतिक परिदृश्य रचते हैं। इस चुनाव में एनडीए ने 202 सीटें, राजद ने 25, कांग्रेस ने 05 सीट जीती। यह परिणाम 2020 की तुलना में कहीं अधिक निर्णायक हैं और विपक्ष के लिए स्पष्ट संदेश भी। कहा जा सकता है कि कमलनाथ जैसे नेताओं को चुनाव से दूर रखना भी पार्टी के लिए नुकसानदायक रहा।

राहुल गांधी के बचकाने भरे फैसलों ने अपने साथ-साथ महागठबंधन को भी अर्श से फर्श पर ला दिया

विकास और नेतृत्व पर जनविश्वास

बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा की संयुक्त राजनीतिक पकड़ एक बार फिर मजबूत होती दिखी। एनडीए की जीत दर्शाती है कि जनता ने उनके अनुभव, सुशासन मॉडल और स्थिर नेतृत्व पर भरोसा जताया है। एनडीए के पक्ष में कई कारक निर्णायक साबित हुए। नीतीश कुमार का प्रशासनिक अनुभव, बीजेपी की संगठनात्मक शक्ति, एनडीए की समन्वित चुनाव रणनीति और सबसे बढ़कर, विपक्ष की खामियों का लाभ। एनडीए मतदाता समूहों तक अपने संदेश को प्रभावी ढंग से पहुंचा सका। महिलाओं, युवा वर्ग और गरीब तबके के लिए चलाई गई योजनाओं ने राजनीतिक रूप से लाभ पहुंचाया। ऊर्जावान प्रचार, केंद्र और राज्य के संयुक्त नेतृत्व की ताकत और उम्मीदवारों के चयन में सटीकता ने जीत का रास्ता आसान किया। (शेष पेज 2 पर)

कमलनाथ जैसे अनुभवी नेताओं की कमी भी खली

माड़वी हिड़मा के खत्म होने से शुरू हो गई नक्सलवाद की उल्टी गिनती

छत्तीसगढ़ में मार्च 2025 तक होना है नक्सलवाद का खात्मा

-ब्यूरो रिपोर्ट

कुख्यात नक्सली माड़वी हिड़मा को सुरक्षाबलों ने एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। माड़वी हिड़मा की मौत देश में नक्सलवाद के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है और इससे नक्सलियों की सैन्य क्षमताएं कमजोर होंगी। हाल के वर्षों में देश में हुई हर बड़ी नक्सली घटना के पीछे माड़वी हिड़मा का ही दिमाग माना जाता है। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल सुरक्षाबलों ने छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर हुई एक मुठभेड़ में देश के सबसे खतरनाक और वांछित नक्सली कमांडर माड़वी हिड़मा को ढेर कर दिया। माओवादियों को यह हाल के वर्षों में लगा सबसे बड़ा झटका है और दावा किया जा रहा है कि माड़वी हिड़मा की मौत के बाद अब देश में नक्सलवाद की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है।

कौन था माड़वी हिड़मा?

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में जन्में माड़वी हिड़मा ने 16 साल की उम्र में ही हथियार उठा लिए थे और बतौर कैडर शुरुआत करके माड़वी हिड़मा बीते दो दशकों में प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) में कई अहम पदों पर रहा। हिड़मा कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था और उस पर सरकार ने एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था। माड़वी हिड़मा सीपीआई माओवादियों की बटालियन नंबर एक का कमांडर था, जो नक्सलियों की सबसे खतरनाक सैन्य टुकड़ी मानी जाती है। हिडमा दंडकारण्य क्षेत्र के घने जंगलों में रहता था और उसे अबूझमाड़ और सुकमा-बीजापुर के वन क्षेत्रों की काफी जानकारी थी। यही वजह थी कि कई कोशिशों के बाद भी हिडमा लंबे समय तक सुरक्षाबलों से बचता रहा। हिडमा फिलहाल बस्तर दक्षिण इलाके में सक्रिय था। (शेष पेज 2 पर)

उज्जैन के किसानों के जिद और जज़्बे के आगे मोहन सरकार नतमस्तक

(पेज 1 का शेष)

यही वह बिंदु था जहां किसानों ने महसूस किया कि उनकी लड़ाई केवल खेतों तक सीमित नहीं बल्कि लोकतांत्रिक आवाज की लड़ाई भी है।

मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश

जब पत्रकारिता सत्ता को सच दिखाती है तो अक्सर सत्ता असहज हो जाती है। यही हुआ उज्जैन में। सरकार के दबाव में काम कर रहे स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने किसानों के आंदोलन में शामिल होने गई मुझे गिरफ्तार करने का कायरतापूर्ण प्रयास किया। यह घटना न केवल लोकतंत्र के चार स्तंभों में से एक मीडिया पर हमला था बल्कि किसानों की आवाज को दबाने की भी कोशिश थी। परंतु जिस साहस के साथ किसानों ने अपनी जमीन की रक्षा की, उसी साहस के साथ मैंने पत्रकारिता के धर्म को निभाया। गिरफ्तारी की कोशिश ने सरकार की छवि को और अधिक कलंकित किया और जनता के बीच यह संदेश गया कि सरकार विकास के नाम पर असहमति को कुचलने पर उतारू है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज कर लिया था लैंड पुलिंग का फैसला

सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के नाम पर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उज्जैन के ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे पक्के निर्माण और बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की योजना को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक गंभीर संवैधानिक प्रश्न खड़ा कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही धार्मिक आयोजनों में अनावश्यक पक्के निर्माण पर रोक लगाने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के स्पष्ट निर्देश दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद मोहन सरकार ने 500 से अधिक किसानों की लगभग 2300 हेक्टेयर से ज्यादा उपजाऊ कृषि भूमि को अधिग्रहित करने की योजना बनाई थी। यह कदम न केवल किसानों की आजीविका पर सीधा प्रहार था, बल्कि न्यायालय की भावना के विपरीत भी माना गया। सरकार की इस कार्यवाही को लेकर सवाल यह भी उठे कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी थी और क्या स्थानीय किसानों से उनकी सहमति वास्तव में ली गई थी। विरोध बढ़ने पर यह मुद्दा राज्य से निकलकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन तक पहुँच गया, जिसने अंततः सरकार के फैसले पर पुनर्विचार की स्थिति उत्पन्न कर दी।

दिल्ली से मिली फटकार और बदल गया सरकार का फैसला

मामला जब धीरे-धीरे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनने लगा, तब सरकार के शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बढ़ा। दिल्ली से स्पष्ट संकेत मिले कि ऐसी संवेदनशील स्थिति में बल प्रयोग या विवादास्पद निर्णय पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी फटकार के बाद मध्यप्रदेश सरकार का रुख बदला और लैंड पुलिंग परियोजना को वापस लेने का निर्णय लिया गया। यह फैसला भले ही एक प्रशासनिक आदेश के रूप में आया हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह संघर्ष की जीत थी किसानों की, पत्रकारिता की और लोकतांत्रिक मूल्यों की।

उज्जैन के किसानों की जीत जिद, जज्बे और मिट्टी से जुड़ाव का परिणाम

आज यह उदाहरण बन चुका है कि जब जनता एकजुट होकर आवाज उठाती है। जब पत्रकारिता ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाती है और जब सत्ता जनभावनाओं को समझने पर मजबूर होती है तब किसी भी प्रकार का अन्यायात्मक निर्णय पलट सकता है। उज्जैन के किसानों ने यह साबित किया कि वे जमीन के खरीदार नही उसके रक्षक हैं। उन्होंने साफ कहा था कि "सिंहस्थ हो, विकास हो, स्वागत है लेकिन हमारी जमीन हड़पकर नहीं।" सरकार अब किसानों की मंशा के अनुसार नई भूमि चयन प्रक्रिया अपनाएगी। यह वह मॉडल होगा जिसमें किसान साझेदार होंगे, शिकार नहीं।

राजनीतिक–प्रशासनिक विफलता की खुली किताब

लैंड पुलिंग परियोजना ने कई सवाल भी छोड़ दिए क्या प्रशासन को इतनी विशाल योजना किसानों से बिना संवाद किए लागू करने का अधिकार था? क्या सरकार ने संवेदनशील क्षेत्र में जनता की भावनाएं समझने का प्रयास किया? क्या लोकतांत्रिक ढांचे में मीडिया की आवाज को दबाना स्वीकार्य है? इन सवालों के जवाब भविष्य में प्रशासन की नीति और सरकार की कार्यशैली तय करेंगे। उज्जैन की यह जीत सिर्फ जमीन की नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जीत है। यह वह कहानी है जिसमें किसान, पत्रकार और समाज एकजुट होकर सत्ता के उस दबाव के सामने खड़े हुए, जिसे गलत दिशा में मोड़ दिया गया था। और अंततः किसानों की विजयी हुई।

एनडीए की ऐतिहासिक जीत और राजद-कांग्रेस का डांवाडोल होता राजनीतिक भविष्य

(पेज 1 का शेष)

राजद की करारी हार वोट मिले, सीटें नहीं

राजद, जो कभी बिहार की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति थी, इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अपना सबसे खराब प्रदर्शन करने के लिए विवश दिखी। 2020 में 75 सीटें जीतने वाली पार्टी 2025 में मात्र 25 सीटों पर सिमट गई। हालांकि उसके वोट शेयर में बहुत भारी गिरावट नहीं आई। 2020 के 23.5% के मुकाबले इस बार लगभग 0.75% की कमी रही लेकिन इस वोट बैंक को सीटों में तब्दील करने में पार्टी बुरी तरह विफल रही। राजद की मजबूती से संबंधित दो बड़े तथ्य सामने आते हैं। वोट शेयर ऊँचा रहा, परंतु रणनीतिक रूप से सीट रूपांतरण बेहद कमजोर। जमीनी पकड़ अभी भी है, लेकिन जातीय समीकरणों और क्षेत्रीय प्रभाव को सही तरह से भुनाया नहीं जा सका। तेजस्वी यादव जिस तेजी से उभरते हुए युवा नेता माने जा रहे थे, इस चुनाव ने उनकी रणनीतिक क्षमता पर सवाल उठा दिए हैं। युवा नेताओं की अपील और सामाजिक न्याय की उनकी राजनीति को वह धार नहीं मिल सकी जिसका पार्टी इंतजार करती है। कभी बिहार की राजनीति पर राज करने वाली राजद आज अस्तित्व की चुनौतियों से जूझ रही है।

कांग्रेस गठबंधन के भरोसे अपना वजूद खोती पार्टी

बिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। कांग्रेस ने महागठबंधन के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन इस सहभागिता का उसे कोई लाभ नहीं मिला बल्कि राजनीतिक नुकसान ही हुआ। कांग्रेस की हार के कारणों में शामिल है। नेतृत्व का कमजोर होना, रणनीति का अभाव, जमीनी स्तर पर संगठन की निष्क्रियता और सबसे बड़ा कारण उम्मीदवार चयन में नेतृत्व की असफलता। चुनाव से पहले पार्टी में बड़ा फेरबदल किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस चुनाव में वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को कम महत्व दिया। कमलनाथ, सचिन पायलट, अशोक गहलोत जैसे नेता चुनावी रणनीति से दूर रखे गए। इसके अलावा, मध्यप्रदेश कांग्रेस की टीम जीतू पटवारी, उमंग सिंघार आदि को बिहार में स्टार प्रचारक के रूप में उतारा गया, लेकिन वे एक भी सीट जीतवाने में सफल नहीं रहे। कांग्रेस का यह प्रदर्शन पार्टी नेतृत्व के लिए चेतावनी है कि यदि उसने अभी भी अपनी "आंखों पर चढ़ी पट्टी" नहीं हटाई तो आने वाले चुनावों में भी यही हाल रहेगा।

महागठबंधन की असफलता तालमेल की कमी और रणनीति का अभाव

राजद और कांग्रेस का गठबंधन इस चुनाव में चुनावी

गणित के स्तर पर तो भारी दिखता था, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट थी। महागठबंधन की विफलता के प्रमुख कारण सीट-बंटवारे में विवाद और असंतोष, कांग्रेस ने अपनी क्षमता से अधिक सीटें मांगीं, राजद ने सहयोगियों की नाराजगी को नजरअंदाज किया, नेतृत्व में समन्वयहीनता, तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच अभियान को लेकर स्पष्ट रणनीति नहीं थी। वोट बैंक का गैर-समेकन, राजद का वोट बिखरा और कांग्रेस अपना वोट बैंक बचा नहीं सकी। प्रचार में ऊर्जा की कमी, एनडीए की तुलना में महागठबंधन प्रचार, एजेंडा और संदेश के स्तर पर कमजोर साबित हुआ। इन सभी कारकों ने गठबंधन को जीत से बहुत दूर कर दिया।

नीतीश-भाजपा समीककरण की दृढ़ता और विपक्ष का भविष्य

नीतीश कुमार और भाजपा का साथ एक बार फिर जनता ने स्वीकार किया है। भाजपा का बढ़ता वोट शेयर और उसकी सीटों में तेजी से बढ़ोतरी दर्शाता है कि उसका जनाधार नींव से मजबूत हो रहा है। जदयू और भाजपा का तालमेल, चाहे राजनीतिक उतार-चढ़ावों से भरा रहा हो, लेकिन जनता दोनों को मिलकर बिहार के लिए स्थिरता और सुशासन की गारंटी मानती है। उधर विपक्ष का भविष्य आज पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। राजद को अपने संगठन, रणनीति और नेतृत्व में बड़े बदलाव करने होंगे। कांग्रेस को बिहार की राजनीति में नई शुरुआत की जरूरत है, अन्यथा उसका वजूद सिर्फ कागजी रह जाएगा। वाम दलों की उपस्थिति प्रतीकात्मक से ज्यादा कुछ नहीं रही चुनाव इस बात का प्रमाण है कि जनता अब सिर्फ नारों, वादों और जातीय राजनीति से आगे देखना चाहती है। वह स्थिरता, विकास और सुशासन के भरोसे पर वोट कर रही है। राजद और कांग्रेस को अब इस हकीकत को स्वीकार करना होगा कि केवल वोट बैंक काफी नहीं, मजबूत संगठन और प्रभावी नेतृत्व भी जरूरी हैं।

माड़वी हिड़मा के खत्म होने से शुरू हो गई नक्सलवाद की उल्टी गिनती

(पेज 1 का शेष)

दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ पर हमले समेत कई बड़े हमलों का था मास्टरमाइंड

हिड़मा कितना खतरनाक था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल के वर्षों के अधिकतर बड़े नक्सली हमलों में उसकी संलिप्तता था फिर चाहे वो साल 2010 में दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ पर हुआ हमला हो, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवानों बलिदान हुए थे या फिर दरभा घाटी में झीरम घाटी का हमला, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूरे कांग्रेस नेतृत्व को खत्म कर दिया गया था। साल 2017 में सुकमा में हुए दो हमलों, जिनमें 37 जवानों की मौत हुई थी और 2021 के बीजापुर में तर्रेम हमले में भी माड़वी हिड़मा का नाम सामने आया था। सुरक्षाबलों का दावा है कि अप्रैल 2025 में करेंगुट्टा पहाड़ी पर हुई मुठभेड़ में हिड़मा बाल-बाल बच गया था। उस मुठभेड़ में 31 माओवादी मारे गए थे। कुख्यात नक्सली माड़वी हिड़मा को सुरक्षाबलों ने एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। माड़वी हिड़मा की मौत देश में नक्सलवाद के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है और इससे नक्सलियों की सैन्य क्षमताएं कमजोर होंगी। माओवादियों को यह हाल के वर्षों में लगा सबसे बड़ा झटका है और दावा किया जा रहा है कि माड़वी हिड़मा की मौत के बाद अब देश में नक्सलवाद की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है।

नक्सलवाद की उल्टी गिनती शुरू

बस्तर रेंज के आईजीपी सुंदरराज पी का कहना है कि माड़वी हिड़मा की मौत नक्सलवाद के लिए बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि कई कुख्यात माओवादी हाल के समय में ढेर हो चुके हैं और कई मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। अब बाकी बचे नक्सली कमांडरों से भी आत्मसमर्पण की अपील की जाएगी और जो अभी भी हिंसा के रास्ते पर चलेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिडमा की मौत से बस्तर क्षेत्र में माओवादी गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। सरकार ने साल 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य तय किया और माड़वी हिड़मा की मौत उस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि हिडमा की मौत के साथ ही देश में नक्सलवाद की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है।

गोंड समाज का इतिहास अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली रहा है: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर के टिकरापारा स्थित गोंडवाना भवन में छत्तीसगढ़ गोंड समाज कल्याण समिति द्वारा आयोजित गोंड युवक-युवती परिचय सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री का पारंपरिक जनजातीय रीति-रिवाजों के अनुसार स्वागत किया गया तथा उन्होंने भगवान बूढ़ादेव का पूजन कर विधि-विधान से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गोंड समाज को सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए 05 लाख रुपये की सहयोग राशि प्रदान करने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधीय पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम द्वारा लिखित दो महत्वपूर्ण पुस्तकों—"आदिवासी

ऐतिहासिक निरंतरता से वर्तमान चुनौतियों तक" तथा "विरासत का सम्मानः वैश्विक दृष्टिकोण पर सवाल" का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गोंड समाज का इतिहास अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली रहा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जनजातीय समाज के हितों के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। देश के सर्वोच्च पद पर जनजातीय समाज की गौरवपूर्ण उपस्थिति इस सम्मान का प्रत्यक्ष प्रतीक है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पीएम जनमन और प्रधानमंत्री धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के माध्यम से जनजातीय समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान हेतु भी सरकार ने कई विशेष पहल प्रारंभ की हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय नायकों के गौरवशाली इतिहास को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उपस्थित लोगों से नया रायपुर में स्थापित जनजातीय संग्रहालय का भ्रमण करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय वीरों ने सदैव अपनी माटी और संस्कृति की रक्षा की है, और इस गौरवमयी परंपरा की सुंदर झलक आपको संग्रहालय में देखने को मिलेगी। श्री साय ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाने वाला जनजातीय गौरव दिवस आदिवासी समाज की विरासत को सम्मान देने का एक सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज को आपस में जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इससे भावी पीढ़ी अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक जड़ों से परिचित होती है। युवक-युवती परिचय सम्मेलन समुदाय के लोगों को एक-दूसरे को समझने, जानने और रिश्तों के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए आयोजकों को शुभकामनाएँ भी दीं।

इस अवसर पर आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधीय पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम ने गोंड समाज के गौरवशाली इतिहास पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि गोंड समाज का इतिहास समृद्ध परंपराओं और वीरता की गाथाओं से भरा हुआ है। उन्होंने बताया कि ऐतिहासिक कालखंडों में गोंड राजाओं ने शासन, प्रबंधन और सामाजिक संरचना को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनका उल्लेख विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजों में मिलता है। मरकाम ने कहा कि डबल-इंजन की सरकार में जनजातीय समुदाय के हितों, विकास और उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ आज बड़े पैमाने पर जनजातीय समाज तक पहुँच रहा है। उन्होंने समाज को एकजुट होकर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया तथा गोंड समाज द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों, सामुदायिक प्रयासों एवं नवाचारों की जानकारी देते हुए कहा कि सामूहिक प्रयास ही समाज को सशक्त बनाते हैं।

सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के साथ आगे बढ़ रहा है प्रदेश: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

-कैलाशचंद्र जैन

जगत प्रवाह. विदिशा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की भावना के अनुरूप प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव विदिशा जिले के कागपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ग्राम पंचायत कागपुर में क्षेत्र के 39.80 करोड़ रुपए की लागत के 137 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आदर्श ग्राम पंचायत कागपुर के लिए एक बड़ी सौगात मिली है, जिससे आदर्श ग्राम पंचायत के रहवासियों को और अधिक सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में धार्मिक स्थलों का विकास किया जाएगा। भगवान राम और कृष्ण की जहां-जहां लीलाएं हुई हैं वहां धाम बनाए जाएंगे। प्रदेश में गीता जयंती को धूमधाम से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि प्रदेश के हर गांव और खेत तक पानी पहुंचाने का संकल्प राज्य सरकार ने लिया है। प्रदेश में जल संरक्षण और जलस्रोतों के विकास का कार्य भली भांति किया गया है। पानी की एक-एक बूंद को संरक्षित किया जा रहा। केन बेतवा परियोजना के माध्यम से विदिशा जिले में सिंचाई के लिए कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की हर पंचायत में वर्ष 2026 तक शमशान घाटों की सड़कों सहित सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएगी। विकास का कोई भी क्षेत्र अधूरा नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि प्रदेश के सांदीपनि विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहे हैं। डॉ भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के माध्यम से गोपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में सड़कों, स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा और अन्य सभी बुनियादी सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। रोजगार के साधन बढ़ाए जाएंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रदेश में विकास की अवधारणा ने मूर्ति रूप लिया है। प्रदेश में जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के जो भवन स्वीकृत हुए हैं वह अच्छी गुणवत्ता के बना रहे हैं। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में निरंतर विकास हो रहा है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था खराब होने से मरीज हो रहे परेशान

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। तहसील क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था खराब होने से मरीज परेशान प्राथमिक हो रहे हैं। स्वास्थ्य केन्द्र में प्राथमिक उपचार ही नहीं मिल पा रहा है। दरअसल रहटगांव एक तहसील है यहां पर इस तहसील से सैकड़ों की संख्या में ग्राम जुड़े हुए हैं। आसपास दर्जनों ग्रामों के लोगों का स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए एकमात्र सहारा रहटगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो वर्तमान में अव्यवस्थाओं से घिरा हुआ है। इस अस्पताल में ना कोई स्वास्थ्य कर्मचारी समय पर मिलता है न हीं मरीज को समय पर इलाज मिल पा रहा है। विगत रात्रि को रहटगांव अस्पताल में डॉक्टर और नर्स की अनुपस्थिति के कारण नवजात शिशु की मृत्यु के मामले को लेकर आज बुधवार को सर्व समाज कि नागरिकों ने अस्पताल में जाकर धरना आंदोलन किया, नारेबाजी की, इस दौरान पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद रहा। नायब तहसीलदार रश्मि धुर्वे को लिखित रूप में ज्ञापन दिया यहां पर में मुख्य मुद्दे में कैलाश कलम निवासी पोनसा डाना की पत्नी प्रेमवती अस्पताल पहुंची थी जहां पर डॉक्टर और नर्स की अनुपस्थिति के कारण नवजात शिशु की मृत्यु हो गई है इसमें जो भी दोषी है उन पर तत्काल कार्रवाई करें और यहां अस्पताल में डॉक्टर सहित नर्स की मौजूदगी रहना चाहिए वह की जाए। जयस संगठन सहित ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचे तो पूरा अस्पताल खाली पड़ा हुआ था। इस दौरान जयस संगठन के जय उइके, राकेश ककोड़िया, राम प्रसाद काजले ने बताया कि समय पर तहसील स्तर का अस्पताल होने के बाद भी प्रभारी डॉक्टर स्टाफ नहीं मिल पाते हैं ,तो बड़ी घटनाएं घट रही हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी है पर डॉक्टर मौजूद नहीं है। सर्दी जुकाम के मरीज कहां जाएं वायरल बुखार चल रहा है मरीज अस्पताल पहुंचते हैं पर इलाज नहीं होता। अस्पताल को कई अवार्ड मिल चुके हैं पर व्यवस्थाएं शून्य है। ग्रामीणों की मांग है कि अस्पताल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा मिलना चाहिए। यहां पर प्रभारी डॉक्टर की नियुक्ति शीघ्र होना चाहिए। अस्पताल में जो भी स्टॉप है वह सही समय पर मौजूद होना चाहिए। यहां पर पहले एक डॉक्टर मौजूद थे जिनका ट्रांसफर हो चुका है। अब कोई भी प्रभारी डॉक्टर नहीं है। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की उपलब्धता बहुत जरूरी है क्योंकि मरीज को प्राथमिक उपचार मिल जाता है तो उसका जीवन बच सकता है। लोग आए दिन जिम्मेदार अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करवा रहे हैं लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई हैं। जिम्मेदार जिला चिकित्सा अधिकारी को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। शीघ्र अस्पताल की व्यवस्था में सुधार नहीं किया जाता है तो ग्रामीण आंदोलन तक करने के लिए बात कह रहे हैं। अभी वर्तमान में तो यह अस्पताल भगवान भरोसे ही चल रहा है।

हायर सेकेंडरी स्कूल में अनियमितता का अम्बार, प्राचार्य प्रभार के बाद भी नदारद

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. गाडरवारा। विकासखंड साईखेड़ा के अंतर्गत तुमड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल से शिकायतों की लंबी फेहरिस्त सामने आ रही है। अभिभावकों व विद्यार्थियों के अनुसार प्रभारी प्राचार्य घर रहते हैं और घर से ही स्कूल का संचालन कर रहे हैं। सूत्रों से पता चला हैं प्रभारी प्राचार्य ड्यूटी के समय घर पर रहते हैं, ऊपर से शिक्षा विभाग कि मेहराबानी तो देखिये इतनी उजागर अनियमितताओं के बावजूद इन्हें वेतन पूरा मिल रहा हैं। एक तरफ जहां बोर्ड परीक्षाएं अब सर पर हैं जिसमें सम्पूर्ण विद्यालय परिवार से शैक्षणिक कार्य के साथ अपने विद्यार्थियों के भविष्य के लिए सजगता से अध्यापन कार्य को पूर्ण कराने के साथ अवलोकन व निरीक्षण की उम्मीदें अभिभावकों को होती हैं। वहां संस्था के प्रमुख व्यक्ति का यह नियमों के विरुद्ध व्यवहार व अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता व्यवस्था की दयनीय स्थिति को उजागर करती है। साथ ही जिम्मेदारों जिनका काम ऐसे अनियमित व नीतिविरुद्ध आचरण करने वाले विभाग के कर्मियों के कार्यों पर अंकुश लगाना है व व्यवस्था निर्माण में सहयोग देना है वह भी अपने अनदेखे नजरिये से ऐसे लोगों को शह देकर बढ़ावा दे रहे हैं। अब देखना होगा कि कब तक यह व्यवस्था यूं ही लचर बनी रहेगी या इस पर जल्द ही कोई कार्यवाही देखने को मिलेगी।

सम्पादकीय

बिहार चुनावः सुशासन पर फिर लगी मुहर

बिहार ने एक बार फिर लोकतंत्र के प्रति अपनी परिपक्वता और विवेक का ऐसा प्रदर्शन किया है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हालिया चुनाव परिणामों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को मिला स्पष्ट जनमत न केवल राजनीतिक स्थिरता का संकेत देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि बिहार की जनता अब विकास, सुशासन और जवाबदेही को प्राथमिकता देती है। यह जनादेश एक तरह से उस यात्रा की पुनर्पुष्टि है, जिसका आरंभ पिछले डेढ़ दशक में सुशासन के सूत्रों के साथ हुआ था और जिसने बिहार को पिछड़ेपन की छवि से बाहर निकालकर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया। इस चुनाव में सबसे उल्लेखनीय यह रहा कि मतदाताओं ने जातिगत समीकरणों, क्षणिक नारों और वादों के बजाय उस नीति-दृष्टि पर भरोसा जताया, जिसने राज्य में वर्षों से स्थायित्व और सुधार की नींव रखी है। एनडीए के पक्ष में आए जनमत की स्पष्टता बताती है कि जनता यह भली-भांति समझ चुकी है कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह की सरकार और किस प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता है। नीतीश कुमार का लंबे समय का प्रशासनिक अनुभव, केंद्र सरकार के सहयोग से लागू अनेक कल्याणकारी योजनाएँ तथा प्रदेश में कानून-व्यवस्था एवं आधारभूत संरचना के विस्तार ने मतदाताओं में विश्वास की भावना मजबूत की है।

बिहार लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता, अपराध और अविकास से जूझता रहा है। लेकिन पिछले वर्षों में जिस प्रकार सड़कों, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिला है, उसने लोगों को यह समझ दी है कि बदलाव संभव है- और नीतियों पर टिके रहने वाली सरकार ही यह बदलाव ला सकती है। हालिया जनमत इसी आशा को पुनः मजबूत करता है। यह विश्वास की पुष्टि है कि विकास को निरंतरता चाहिए, और उसका नेतृत्व ऐसे हाथों में होना चाहिए जो राज्य की सामाजिक विविधता को समझते हों और निर्णयों में स्थिरता रखते हों। एनडीए की जीत इस बात का भी प्रतीक है कि केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बिहार के विकास के लिए कितना अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र द्वारा शुरू की गई योजनाएँ चाहे वह गरीब कल्याण से जुड़ी हों, अधोसंरचना से या रोजगार व कौशल विकास से बिहार में प्रभावी रूप से लागू हुई हैं। इन योजनाओं के जमीनी असर ने यह एहसास कराया है कि विकास अब केवल कागजों में नहीं, बल्कि जीवन में उतर सकता है। यही कारण है कि मतदाता ने एनडीए के पक्ष में स्थिर जनादेश देकर राज्य और केंद्र के समन्वय को जारी रखने की इच्छा जताई है। सत्ता परिवर्तन लोकतंत्र का स्वभाव है, लेकिन विवेकपूर्ण जनमत ही लोकतंत्र की शक्ति है। बिहार के लोगों ने इसी शक्ति का परिचय देते हुए एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि वे उन नीतियों और नेतृत्व को आगे देखना चाहते हैं जो जाति-वर्ग की खाईयों को पाटकर सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करे। यह जनादेश इस बात का भी संकेत है कि युवा मतदाता अब विकास, रोजगार और स्वाभिमान को केंद्र में रखकर अपने निर्णय ले रहा है। वह राजनीति के पुराने ढर्रों से दूर होता जा रहा है और नई दृष्टि के साथ बदलाव को स्वीकार कर रहा है।

हालाँकि सुशासन की यह यात्रा अभी अधूरी है। बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि और रोजगार के क्षेत्र में बड़े सुधार की आवश्यकता है। इस जनमत ने एनडीए को यह जिम्मेदारी भी सौंपी है कि वह अपनी उपलब्धियों को आधार बनाकर आने वाले वर्षों में और साहसिक कदम उठाए। नौकरियों, निवेश और औद्योगिक विस्तार की दिशा में ठोस कार्ययोजना राज्य को नई ऊँचाइयों पर ले जा सकती है। साथ ही, सुशासन की असली परीक्षा पारदर्शिता, समयबद्धता और जनता से संवाद में निहित होती है, जिसे बनाए रखना नई सरकार के लिए अनिवार्य होगा। समग्र रूप से देखें तो बिहार के मतदाताओं ने स्थिरता, प्रगति और सुशासन को प्राथमिकता देते हुए एक परिपक्व राजनीतिक संदेश दिया है। एनडीए के नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार के सामने अवसर भी है और चुनौती भी। अवसर यह कि मजबूत जनमत के सहारे वह आगामी वर्षों में बड़े परिवर्तन कर सकती है और चुनौती यह कि इस विश्वास की कसौटी पर खरा उतरने के लिए उसे निरंतर गति, पारदर्शिता और जनोन्मुखी प्रशासन का पालन करना होगा। यदि सरकार ने इस जनमत की भावना को समझते हुए अपनी नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाया, तो निस्संदेह बिहार आने वाले वर्षों में एक सुशासन-प्रधान, विकसित और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में उभरकर सामने आएगा।

सियासी गहमागहमी

बघेल की जल्द हो सकती है गिरफ्तारी

पिछले पांच सालों में मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भूपेश बघेल ने जो भी भ्रष्टाचार के कार्यों को अंजाम दिया है अब उनकी परते खुलना शुरू हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार महादेव सट्टा एप मामले में प्रमुख आरोपी रहे बघेल को सीबीआई की एक टीम कभी भी गिरफ्तार करने रायपुर पहुंच सकती है। बघेल को अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा है शायद यही वजह है कि वे लगातार कांग्रेस आलाकमान के आगे पीछे होकर खुद को राज्यसभा कोटे से संसद भवन तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं। जानकारी के अनुसार बघेल के अलावा उनके करीबी लोगों पर भी एक बार फिर सीबीआई की एक टीम शिकंजा कस सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि बघेल सीबीआई के इस जाल से खुद को किस तरह से बचा पाते हैं।

अति आत्म विश्वास ले डूबा तेजस्वी को

बिहार की राजनीति का रंग हमेशा अलग होता है यहाँ हवा की दिशा बदलते ही नेता भी अपने तेवर बदल लेते हैं। मगर इस बार के विधानसभा चुनाव में नतीजों ने जिस चेहरे का 'पॉलिटिकल मेकओवर' किया है, वह हैं तेजस्वी यादव। चुनाव से पहले तक जिस आत्मविश्वास को वे "परिवर्तन की लहर" समझ बैठे थे, नतीजों ने उसे एक झटके में "घमंड की फुसफुसाहट" साबित कर दिया। तेजस्वी यादव को भरोसा था कि युवा उन्हें कंधों पर उठाकर सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचा देंगे। घोषणाएँ इतनी कि मानो चुनाव नहीं, कोई मेगा सेल का उद्घाटन हो रहा हो। रैलियों में उनकी मुस्कान और विपक्ष पर तंज मानो बता रहे हों" अबकी बार बस मैं ही मैं।" लेकिन लोकतंत्र के असल मालिक मतदाताओं ने आखिरकार अहंकार की इस हवा में एक तेज झोंका मारा, और नतीजों ने तस्वीर साफ कर दी। जनता ने बता दिया कि राजनीति में सिर्फ भाषणों का तापमान नहीं चलता, काम का थर्मामीटर भी देखना पड़ता है। युवा नेतृत्व की छवि अच्छी बात है, पर अनुभव को हवा में उड़ाना जनता के स्वभाव में नहीं। तेजस्वी को यह भी समझ आ गया कि सोशल मीडिया की तालियाँ और मैदान की वोटिंग में बड़ा फर्क होता है। नतीजों के बाद उनकी चुप्पी भी बहुत कुछ बोल गई वही तेज आवाज़ अचानक "रीसेट मोड" में चली गई।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

BJP के लाखों लोग खुलेआम अलग-अलग राज्यों में घूम-घूमकर वोट डालते हैं।
और इस चोरी को छुपाने के लिए सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं।
BJP और EC मिलकर खुलेआम vote चोरी कर रहे हैं - लोकतंत्र की हत्या लाइव चल रही है।

-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

भाजपा सरकार में मध्य प्रदेश घोटालों का प्रदेश बनता जा रहा है। अब स्टांप पेपर घोटाला सामने आया है।
राजधानी में एक ऐसे गैंग का पकड़ा जाना जो पहले से उपयोग में आ चुके पुराने या नकली स्टांप को उपयोग कर रहे हैं और राजस्व का नुकसान पहुँचा रहे हैं, चिंता का विषय है।

-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

निर्मला सीतारमण : एक साधारण महिला की छलांग जिसने वित्त मंत्रालय में बनाई अपनी जगह

समता पाठक/जगत प्रवाह

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में उन्होंने अपना 65वां जन्मदिवस मनाया। देश भर से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा "केन्द्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। निर्मला जी विकास और सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास कर रही हैं। निर्मला सीतारमण का जन्म तमिलनाडु के एक साधारण परिवार में 18 अगस्त 1959 को हुआ था। उनके पिता रेलवे में नौकरी करते थे। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई अलग-अलग शहरों में हुई। इसके बाद उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातक किया और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। यहीं उनका रूझान राजनीति की ओर हुआ। इंडो-यूरोपियन टेक्सटाइल ट्रेड में अपनी पीएचडी पूर्ण की। इसी दौरान उनकी मुलाकात डॉक्टर पराकाला प्रभाकर से हुई, जिन्हें बाद में उन्होंने अपना जीवनसाथी बना लिया। पढ़ाई के दौरान नौकरी भी की और फिर पति के साथ लंदन चली गई। लंदन में उन्हें एक होम हेकोर की दुकान में सेल्स गर्ल का काम करना पड़ा। फिर वो वापस भारत आई और हैदराबाद में सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी में डेप्युटी डायरेक्टर की नौकरी की। निर्मला सीतारमण के सास-ससुर कांग्रेसी नेता थे। उसके बावजूद साल 2008 में निर्मला सीतारमण ने बीजेपी ज्वाइन की, तब उन्हें पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया। साल 2014 में जब केंद्र में बीजेपी का सरकार बनी तो उन्हें मोदी सरकार में अहम जिम्मेदारी दी गई और साल 2016 में वो कर्नाटक सीट से राज्यसभा सदस्य बनी। उसी साल कैबिनेट विस्तार में उन्हें वाणिज्य और उद्योग (स्वतंत्र प्रभार) में राज्यमंत्री बनाया गया। 03 सितंबर 2017 को निर्मला सीतारमण पहली बार देश की पहली पूर्ण रक्षामंत्री बनी। इसके अलावा वो सुखोई- 30 एमकेआई में उड़ान भरने वाली देश की पहली महिला रक्षामंत्री के रूप में उनके नाम अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है। साल 2017 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाली दूसरी महिला बनी।

स्पेशल खबर

उत्तराखंड में अर्धकुंभ से पहले 120 करोड़ में चमकेगा 80 किमी का राष्ट्रीय राजमार्ग

-संवाददाता

जगत प्रवाह, देहरादून। हरिद्वार में होने वाले अर्धकुंभ मेले के लिए 80 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग को 120 करोड़ रुपये की लागत से चमकाया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य सड़क की गुणवत्ता में सुधार करना और तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा को सुगम बनाना है। मरम्मत कार्य में सड़क की सतह को बेहतर बनाना और सुरक्षा उपायों को बढ़ाना शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रामपुर तिराहा (मुजफ्फरनगर) से हरिद्वार सर्वानंद घाट तक लगभग 80 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग के ब्लैक टॉप कार्य को गति दे दी है। करीब 120 करोड़ रुपये की लागत से किए जा रहे इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के तहत ब्लैक टॉप बिछाने का कार्य शुरू हो चुका है। पहले चरण में सर्विस लेन की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसके बाद मुख्य मार्ग पर ब्लैक टॉप का कार्य शुरू होगा। गौरतलब है कि इस हाईवे पर अंतिम बार ब्लैक टॉप कार्य लगभग चार वर्ष पूर्व किया गया था। निरंतर बढ़ते यातायात दबाव और भारी वाहनों की आवाजाही के कारण मार्ग के कई हिस्सों पर गड्ढे उभरने लगे थे, जिससे दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती थी। इसी के मद्देनजर प्राधिकरण ने मार्ग को पूर्ण रूप से सुरक्षित एवं सुगम बनाने के लिए रिन्यूअल कार्य शुरू किया है। इसी क्रम में इस हाईवे की सर्विस लेन, जो कई स्थानों पर जर्जर स्थिति हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जा रहा है। पहले चरण में प्रेमनगर आश्रम से लेकर शंकराचार्य चौक के बीच का कार्य शुरू किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, यह पूरा कार्य

को पूरा करने में एक वर्ष का समय लगेगा, जबकि निर्धारित समयसीमा अक्टूबर 2026 तय की गई है। वर्षाकाल में कार्य गति मौसम की अनुकूलता पर निर्भर करेगी। कार्य के दौरान यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए एनएचएआइ ने यातायात पुलिस के साथ भी मंथन किया है। योजना के अनुसार, कार्य आधे मार्ग पर चलता रहेगा और शेष आधे हिस्से से वाहनों का सुचारु आवागमन होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रुड़की खंड के अधिशासी अभियंता अतुल शर्मा ने बताया कि बिटुमिन सड़क की सामान्य आयु चार से पांच वर्ष होती है। वर्ष 2021 में बने इस हाईवे पर यातायात दबाव अत्यधिक बढ़ चुका है, इसलिए अर्धकुंभ 2027 से पूर्व राजमार्ग को तैयार करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि पूरा प्रोजेक्ट अर्धकुंभ की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है।

नक्सली माओवाद गिनता अंतिम सांसें

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

छत्तीसगढ और आंध्रप्रदेश की सीमा पर हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने षीर्श माओवादी क्रूर हिंसा के प्रतीक बन चुके हिड़मा को मार गिराने के बाद सात अन्य नक्सलियों को मार गिराने के साथ तय है, कि अब नक्सली हिंसा अपने अंतिम चरण में है। मार्च 2026 तक इसका समूल नाश हो जाएगा, क्योंकि अब प्रमुख नक्सली सरगनाओं की गिनती मात्र 3-4 तक सिमट गई है। यदि वे हथियार डालकर समर्पण नहीं करते हैं तो उनका भी अंत होना तय है। हालांकि इस मुठभेड़ में मप्र के बालाघाट में पदस्थ निरीक्षक आशीष शर्मा को बलिदान देना पड़ा है। माओवादी अर्से से देश में एक ऐसी जहरीली विचारधारा रही है, जिसे नगरीय बौद्धिकों का समर्थन मिलता रहा है। ये बौद्धिक नक्सली संगठनों को आदिवासी समाज का हितचिंतक मानते रहे हैं, जबकि जो आदिवासी नक्सलियों के विरोध में रहे, उन्हें इनकी हिंसक क्रूरता का षिकार होना पड़ा है। बावजूद इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि देष के वामपंथी दलों को कभी भी सुरक्षाबलों का नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा सफाये का अभियान पसंद नहीं आया। इससे पहले छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के जंगल में सुरक्षा बलों के नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता तब मिली थी, जब डेढ़ करोड़ के इनामी बसव राजू समेत 27 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। यह कुख्यात दरिंदा होने के साथ गुरिल्ला लड़ाका था। माओवादी पार्टी का इसे पर्याय माना जाता था। इसका नक्सली सफर 1985 से शुरू हुआ था। इसने वारंगल के क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की थी।

नक्सली हिंसा लंबे समय से देश के अनेक प्रांतों में आंतरिक मुसीबत बनी हुई है। वामपंथी माओवादी उग्रवाद कभी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना जाता रहा है। लेकिन चाहे जहां रक्तपात की नदियां बहाने वाले इस उग्रवाद पर लगभग नियंत्रण किया जा चुका है। नई रणनीति के अंतर्गत अब सरकार की कोशिश है कि सीआरपीएफ की तैनाती उन सब अज्ञात क्षेत्रों में कर दी जाएं जहां नक्सली अभी भी ठिकाना बनाए हुए हैं। इस नाते केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सबसे अधिक नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में 4000 से अधिक सैन्यबल तैनात करने जा रहा है। केंद्र सरकार की कोषिष है कि 31 मार्च 2026 तक इस क्षेत्र को पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाए। इतनी बड़ी संख्या में सैन्यबलों की अज्ञात क्षेत्र में पहुंच का मतलब है कि अब इस उग्रवाद से अंतिम लड़ाई होने वाली है। मजबूत और कठोर कार्य योजना को अमल में लाने का ही नतीजा है कि इस साल सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 2024 में 153 नक्सली मारे जा चुके हैं। 2004.14 की तुलना में 2014 से 2024 के दौरान देश में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 53 प्रतिशत की कमी आई है। 2004 से 2014 के बीच नक्सली हिंसा की 16,274 वारदातें दर्ज की गई थीं, जबकि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 सालों में इन घटनाओं की संख्या घटकर 7,696 रह गई। इसी अनुपात में देश में माओवादी हिंसा के कारण होने वाली मौतों की संख्या 2004 से 2014 में 6,568 थीं, जो पिछले दस साल में घटकर 1990 रह गई है और अब सरकार ने जो नया संकल्प लिया हैए उससे तय है कि जल्द ही इस समस्या को निर्मूल कर दिया जाएगा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से आतंक और अलगाववाद खत्म करने की निर्णायक लड़ाई लड़ी थी, वैसी ही स्थिति अब छत्तीसगढ़ में अनुभव होने लगी है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ में नक्सली तंत्र कमजोर हुआ है, लेकिन उसकी शक्ति अभी षेश है। अब तक पुलिस व गुप्तचर एजेंसियां इनका सुराग लगाने में नाकाम होती रही थीं, लेकिन नक्सलियों पर षिकंजा कसने के बाद से इनको भी सूचनाएं मिलने लगी हैं। इसी का नतीजा है कि सैन्यबल इन्हें निशाना बनाने में लगातार कामयाब हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर नक्सली आदिवासी हैं। इनका कार्यक्षेत्र वह आदिवासी बहुल इलाके हैं, जिनमें ये खुद आकर नक्सली बने हैं। इसलिए इनका सुराग सुरक्षाबलों को लगा पाना मुश्किल होता है। लेकिन ये इसी आदिवासी तंत्र से बने मुखबिरों से सूचनाएं आसानी से हासिल कर लेते हैं। दुर्गम जंगली क्षेत्रों के मार्गों में छिपने के स्थलों और जल स्रोतों से भी ये खूब परिचित हैं। इसलिए ये और इनकी शक्ति लंबे समय से यहीं के खाद-पानी से पोषित होती रही है। हालांकि अब इनके हमलों में कमी आई है। दरअसल इन वनवासियों में अर्बन माओवादी नक्सलियों ने यह भ्रम फैला दिया था कि सरकार उनके जंगल, जमीन और जल-स्रोत उद्योगपतियों को सौंपकर उन्हें बेदखल करने में लगी है, इसलिए यह सिलसिला जब तक थमता नहीं है, विरोध की मुहिम जारी रहनी चाहिए। सरकारें इस समस्या के निदान के लिए बातचीत के लिए भी आगे आईं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इन्हें बंदूक के जरिए भी काबू में लेने की कोशिशें हुई हैं। लेकिन नतीजे पूरी तरह अनुकूल नहीं रहे। एक उपाय यह भी हुआ कि जो नक्सली आदिवासी समर्पण कर मुख्यधारा में आ गए थे, उन्हें बंदूकें देकर नक्सलियों के विरुद्ध खड़ा करने की रणनीति भी अपनाई गई। इस उपाय में खून-खराबा तो बहुत हुआ, लेकिन समस्या बनी रही। गोया, आदिवासियों को मुख्यधारा में लाने से लेकर विकास योजनाएं भी इस क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने में अब तक सफल नहीं हो पाई हैं।

इस मुठभेड़ में मारे गए हिड़मा का बस्तर के इस जंगली क्षेत्र में बोलबाला रहा है। वह सरकार और सुरक्षाबलों को लगातार चुनौती दे रहा था, जबकि राज्य एवं केंद्र सरकार के पास मोदी सरकार से पहले रणनीति और दृढ़ इच्छा षक्ति की हमेषा कमी रही थी। तथाकथित षहरी माओवादी बौद्धिकों के दबाव में भी मनमोहन सिंह सरकार रही। इस कारण भी इस समस्या का हल दूर की कौड़ी बना रहा। यही वजह थी कि नक्सली क्षेत्र में जब भी कोई विकास कार्य या चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती थी तो नक्सली उसमें रोड़ा अटका देते थे। अब हिड़मा के मारे जाने के बाद नक्सली समस्या का हल की गुंजाइष बढ़ गई है।

कांग्रेस की पूर्व केंद्र तथा छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार नक्सली समस्या से निपटने के लिए दावा कर करती रही हैं कि विकास इस समस्या का निदान है। यदि तत्कालीन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के विकास संबंधी विज्ञापनों में दिए जा रहे आंकड़ों पर भरोसा करें तो छत्तीसगढ़ की तस्वीर विकास के मानदण्डों को छूती दिख रही है, लेकिन इस अनुपात में यह दावा बेमानी है कि समस्या पर अंकुष विकास की धारा से लग रहा है, क्योंकि इसी दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं को नक्सली बनाए जाने के प्रमाण भी मिले थे। बावजूद कांग्रेस के इन्हीं नक्सली क्षेत्रों से ज्यादा विधायक जीतकर आते रहे थे। हालांकि नक्सलियों ने कांग्रेस पर 2013 में बड़ा हमला बोलकर लगभग उसका सफाया कर दिया था। कांग्रेस नेता महेन्द्र कर्मा ने नक्सलियों के विरुद्ध सलवा जुडूम को 2005 में खड़ा किया था। सबसे पहले बीजापुर जिले के ही कुर्तु विकासखण्ड के आदिवासी ग्राम अंबेली के लोग नक्सलियों के खिलाफ खड़े होने लगे थे। नतीजतन नक्सलियों की महेंद्र कर्मा से दुश्मनी ठन गई थी। इस हमले में महेंद्र कर्मा के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नंदकुमार पटेल और हरिप्रसाद समेत एक दर्जन नेता मारे गए थे। लेकिन कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में अपनी खोई शक्ति फिर से हासिल कर ली थी, बावजूद नक्सलियों पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पाई थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपदस्थ कर भाजपा फिर सत्ता में आई, उसके बाद से ही नक्सलियों के सफाए का सिलसिला चल रहा है। दरअसल, देश में अब तक तथाकथित शहरी बुद्धिजीवियों का एक तबका ऐसा भी रहा, जो माओवादी हिंसा को सही ठहराकर संवैधानिक लोकतंत्र को मुखर चुनौती देकर नक्सलियों का हिमायती बना हुआ था। यह न केवल उनको वैचारिक खुराक देकर उन्हें उकसाने का काम करता था, बल्कि उनके लिए धन और हथियार जुटाने के माध्यम भी खोला था। बावजूद इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जब ये राष्ट्रघाती बुद्धिजीवी पुख्ता सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किए गए तो बौद्धिकों और वकीलों के एक गुट ने देश के सर्वोच्च न्यायालय को भी प्रभाव में लेने की कोशिश की थी और गिरफ्तारियों को गलत ठहराया था। माओवादी किसी भी प्रकार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए जो भी उनके खिलाफ जाता है, उसकी बोलती बंद कर दी जाती हैं। लेकिन अब इस चरमपंथ पर पूर्ण अंकुश लगने जा रहा है।

जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

जलवायु परिवर्तन 21वीं सदी का एक निर्णायक मुद्दा है, जो मौसम के मिजाज को प्रभावित कर रहा है, खाद्य सुरक्षा को ख़तरा पैदा कर रहा है, प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ा रहा है और वैश्विक असमानताओं को बढ़ा रहा है। जलवायु परिवर्तन वह वैश्विक मुद्दा है जो भारत सहित सभी देशों को प्रभावित करता है, जो दुनिया में ग्रीनहाउस गैसों के सबसे बड़े उत्सर्जकों में से एक है। WION की एक रिपोर्ट के अनुसार, यदि उचित कदम नहीं उठाए गए, तो जलवायु परिवर्तन 80 वर्षों में लगभग 8 करोड़ लोगों की जान ले लेगा। भारत ने पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाले जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित और प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्लोबल साउथ की आवाज़ माना जाने वाला भारत, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने पर वैश्विक बातचीत का एक अभिन्न अंग है। जलवायु परिवर्तन से निपटने की इसकी रणनीति के जीएचजी (ग्रीन हाउस गैस) उत्सर्जन को कम करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण परिणाम हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत ने हमेशा दुनिया के समक्ष अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। जी-20, भारत सहित दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है और वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत ने 2030 तक अपनी कार्बन उत्सर्जन तीव्रता, जो कि सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, को 2005 के स्तर से 33-35% कम करने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत ने 2030 तक अपनी 40% ऊर्जा गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का भी संकल्प लिया है। वन एवं वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करने का भी संकल्प लिया है।

ग्लासगो में आयोजित COP26 शिखर सम्मेलन में भारत ने महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएं व्यक्त की है जिनमें शामिल हैं जैसे 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना, 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करना एवं 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी लाना आदि। वर्तमान में, कोयले से हमारी कुल ऊर्जा आपूर्ति में 43.5 प्रतिशत की वृद्धि होती है, इसके बाद जैव-ईंधन और अपशिष्ट (24.7 प्रतिशत), पेट्रोलियम (22.1 प्रतिशत), प्राकृतिक गैस (6.7 प्रतिशत), जल-विद्युत (1.5 प्रतिशत) और परमाणु ऊर्जा (1.2 प्रतिशत) का स्थान आता है। सरकार ने देश के कम से कम 25 प्रतिशत घरों में इन हानिकारक ईंधनों के स्थान पर बिजली पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। भारत की 13वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय विद्युत योजना के मसौदे के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि 2027 तक नवीकरणीय संसाधन भारत की ऊर्जा मांग के आधे से अधिक को पूरा कर लिया जाएगा। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित दो प्रमुख नीतियां क्रियान्वित की हैं: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के लिए रणनीतिक योजना, जो एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है, तथा राष्ट्रीय सौर मिशन, जो नवीकरणीय ऊर्जा के लिए क्षमता लक्ष्य निर्धारित करता है। सरकार ने 25 सौर पार्कों में निवेश किया है, जिनमें भारत की कुल स्थापित सौर क्षमता को लगभग दस गुना बढ़ाने की क्षमता है। वाहन ईंधन और वाणिज्यिक भवनों से संबंधित कानूनों को कड़ा कर दिया गया है। जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत का नेतृत्व वैश्विक स्थिरता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालाँकि, प्रभावी जलवायु कार्रवाई के लिए देशों और हितधारकों के बीच सहयोगात्मक प्रयास अभी भी आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन से निपटना केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है। मज़बूत नीतियों, नवोन्मेषी समाधानों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ, भारत इस वैश्विक संकट से निपटने में मिसाल कायम कर रहा है।

रिटायरमेंट नहीं, यह अनुभव का स्वर्णकाल है

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

भारत राजनीति, व्यापार और सामाजिक नेतृत्व- तीनों ही क्षेत्रों में उम्र और अनुभव को सम्मान देता है। 60 वर्ष से अधिक आयु के नेता जब संसद में बोलते हैं तो उनकी बात दिशा बन जाती है। बड़े उद्योग अपने बोर्ड में अनुभवी लोगों को शामिल करते हैं, क्योंकि संकट की घड़ी में अनुभव ही सबसे विश्वसनीय सलाहकार होता है। समाज में भी वरिष्ठ नागरिक अपनी दृष्टि, अपनी स्मृति और अपनी जीवन-यात्रा से नई पीढ़ी को संभालने का काम करते हैं। लेकिन एक गहरी विडंबना है: पूरे देश में वही सम्मान और वही उपयोग पुलिस तथा प्रशासनिक सेवाओं के रिटायर्ड अधिकारियों को नहीं मिलता जबकि उनका अनुभव सबसे कठिन, सबसे जोखिमपूर्ण और सबसे व्यावहारिक होता है। एक पुलिस अधिकारी 30–35 वर्षों तक अपराध के मनोविज्ञान को समझता है, भीड़ की नब्ज पहचानता है, संवेदनशील परिस्थितियों को शांत करता है, नक्सल क्षेत्रों में रणनीति बनाता है, सामाजिक संघर्षों को संभालता है और हर तरह के अपराध के "ग्राउंड रियलिटी पैटर्न" को अपनी आँखों से देखता है। ये अनुभव किताबों में नहीं पढ़े जाते बल्कि फिल्ड में सीखे जाते हैं और उस अनुभव से युवाओं को प्रेरणा दी जाती है। मध्य प्रदेश सहित देश के हर राज्य में ऐसे हज़ारों रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, जो आज भी ऊर्जा और विवेक से भरपूर हैं। पर रिटायरमेंट के साथ ही यह अमूल्य अनुभव एक तरह से "फाइल बंद" कर दिया जाता है। और यही वह राष्ट्रीय नुकसान है, जिसके समाधान पर अब गंभीरता से सोचना होगा।

अनुभव की कीमत राजनीति और व्यापार समझते हैं, लेकिन पुलिस-प्रशासन क्यों नहीं? राजनीति में वरिष्ठ नेता मार्गदर्शक बनते हैं। कॉर्पोरेट जगत में अनुभवी लोग बोर्ड में शामिल होते हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन में जो नागरिक जीवन की सुरक्षा का संवेदनशील स्तंभ हैं वहीं रिटायर्ड अधिकारियों के अनुभव का व्यवस्थित उपयोग लगभग न के बराबर है। जबकि पुलिस सेवा में अनुभव की कोई बराबरी ही नहीं। क्योंकि अपराधी कैसे सोचता है, दंगों में कौन सी गलती सबसे महँगी पड़ती है, आर्थिक अपराधों के पैटर्न क्या हैं, साइबर अपराधियों की मनोवृत्ति कैसे बदलती है,

सामुदायिक पुलिसिंग में कौन-सी भाषा भरोसा बनाती हैयह सब केवल वही समझ सकता है जिसने इसे जिया है।

मध्य प्रदेश: एक राष्ट्रीय मॉडल बनने की क्षमता

मध्य प्रदेश भौगोलिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक रूप से बहुआयामी राज्य है। यहाँ शहरी अपराध भी हैं, ग्रामीण संवेदनशीलताएँ भी हैं, आदिवासी बेल्ट की विशिष्ट चुनौतियाँ भी हैं, और नक्सल क्षेत्रों का दबाव भी। ऐसे में रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों के अनुभव का उपयोग न केवल ज़रूरी है, बल्कि नवाचार का अवसर भी है। राज्य अगर साहस दिखाए, तो यह मॉडल पूरे भारत के लिए मिसाल बन सकता है।

कहाँ-कहाँ रिटायर्ड अधिकारियों का अनुभव सोना साबित हो सकता है

1. पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों में अतिथि विशेषज्ञ (Guest Faculty)

युवा भर्ती तकनीकी ज्ञान सीख लेते हैं, लेकिन जमीनी अनुभव नहीं मिलता।

रिटायर्ड डीएसपी, एसपी, DIG, IG, ADG यदि पढ़ाएँ—

- वास्तविक केस-स्टडी
- पूछताछ की कला
- क्राइम साइकोलॉजी
- भीड़ प्रबंधन
- महिला–बाल अपराध की संवेदनशीलता

तो पुलिस फोर्स का स्तर कई गुना बढ़ सकता है।

2. जटिल अपराधों की जाँच में Special Expert Panels

हर जिले में 10–15 अनुभवी रिटायर्ड अधिकारियों का पैनल बनाया जाए:

- हत्या व संगठित अपराध
- साइबर फ्रॉड
- नाबालिग अपराध
- महिला अत्याचार
- क्रॉस-डिस्ट्रिक्ट गैंग पैटर्न

अमेरिका, कनाडा, जापान में ऐसा दशकभर से चल रहा है। भारत में CBI/ED भी कई बार रिटायर्ड विशेषज्ञों की मदद लेती हैं। MP इसे जिला स्तर पर लागू कर सकता है।

3. सामुदायिक पुलिसिंग (Social Policing)

विश्वास पुलिसिंग का सबसे बड़ा आधार है।

रिटायर्ड अधिकारी यहाँ "सीनियर एडवाइजर" बन सकते हैं—

- महिलाओं की सुरक्षा अभियान
- ड्रग डी-एडिक्शन प्रयास
- स्कूल–कॉलेज सेफ्टी कमेटी
- साइबर अवेयरनेस
- ट्रैफिक एवं सामाजिक जागरूकता

उनकी विश्वसनीयता जनता के मन में पुलिस के लिए सम्मान बढ़ाती है।

4. नीति निर्माण में Advisory Boards

रिटायर्ड IAS/IPS अधिकारियों को Policy Advisory Council में शामिल किया जाए। नीतियाँ तभी सफल होती हैं जब उनमें फील्ड अनुभव की खुशबू हो।

रिटायरमेंट किसी अधिकारी की क्षमता का अंत नहीं

रिटायरमेंट किसी अधिकारी की क्षमता का अंत नहीं, बल्कि अनुभव की पराकाष्ठा है। जिस राष्ट्र ने अपने अनुभवी लोगों को सम्मान दिया, वही राष्ट्र आगे बढ़ा। मध्य प्रदेश यदि रिटायर्ड अधिकारियों को प्रणालीबद्ध भूमिका दे देता है, तो सिर्फ अपराध नियंत्रण नहीं- बल्कि शासन, प्रशिक्षण और समाज में एक नई संस्कृति विकसित होगी। एक अनुभवी अधिकारी की एक सही सलाह—एक बड़े संकट को रोक सकती है और भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित बना सकती है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। संपादक : विजया पाठक।
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)